(b) what are the major encroachment cases of last three years and what measures are being taken to remove encroachment and what are the preventive measures suggested; and

(c) the number of persons involved in encroachment and actions taken against them during the said period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (c) It is reported that there has been some increase in the area of encroachment on public lands in Delhi.

Information is being collected and will be placed before the Sabha.

Charging of Composition Fee by Delhi Development Authority

1833. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the number of court cases have increased against Delhi Development Authority during the tenure of the present Vice Chairman of Delhi Development Authority; and

(b) in now many cases the Delhi Development Autority has given the extension of time without "issue of Demand Notice" or without taking any undertaking free from the allottees for depositing the composition fee?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) There has been no abnormal increase in the Court cases during the tenure of the present Vice-Chairman, DDA.

(b) Extension of time is generally given on issue of demand notice and on obtaining an undertaking from the allottees to pay the final rates of composition fee. However, in cases where the allottees themselves deposit composition fee for extension of time or where the composition fee has been waived by the competent authority, there is no need to issue any demand notice. No separate record is maintained of such cases.

Violation of ILO Convention of Freedom of Association and Collective Bargaining

1834. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Confederation of Officers Associations of Central Public Sectod Undertaings has submitted a complaint to the Director General, International Labour Odganisation (ILO) in respect of violation of convention 87 (Freedom of Association) and convention 98 (collective bargaining) with regard to the managerial and supervisory staff of the enterprises owned by Government; and

(b) if so, the details thereof; and the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): (a) Yes, Sir.

(b) The Confederation has *inter alia,* alleged that the officers in the public sector undedtakings do not have any effective freedom of association and that any formal association established by them is not given official recognition and accorded any right to collective bargaining. The Industrial Disputes Act does not apply to them. The officers therefor do not have effective remedies including recourse to Industrial Tribunals.

राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा विदेशी मुद्रा की बचत

1835. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र विदेशी मुद्रा की बचत से संबंधित देश की नीति के मामले में सहयोग नहीं कर रहा है और वह अभी भी अनुत्पादक प्रयोजनों के लिए आयातित पैकिंग सामग्री का प्रयोग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पेट्रोलियम उत्पादों और आयातित सामग्री से निर्मित पैकिंग सामग्री तथा स्वदेशी

पैकिंग सामग्री की खरीदों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार, आयातित पैकिंग सामग्री के उपयोग पर प्रतिबंध लगा कर, स्वदेशी सामग्री के प्रयोग को बढ़ावा देने का विचार रखती है यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देब) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

रेल गाड़ी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि

1836. **श्री जिनेन्द्र कुमार जैन :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल गाड़ियों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वार्षिक वृद्धि की अनुमानित दर कितनी है;

(ग) क्या यात्रियों की संख्या में हुई इस वृद्धि के कारण उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने रेल गाड़ियों की संख्या में भी वृद्धि की है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान यात्रियों की संख्या में प्रति वर्ष कितनी वृद्धि हुई है और इस मांग को पूरा करने के लिए औसतन कितनी रेल गाड़ियां बढ़ाई गई हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने चालू वर्ष और आगामी वर्षों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई प्रभावी कार्य योजना तैयार की है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

यात्री यातायात की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त यात्री गाड़ियां चलाई जाती हैं; लेकिन यह परिचालनिक व्यावहारिकता तथा वास्तविक एवं योजना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान यात्रियों की संख्या में वर्षवार वृद्धि/कमी तथा यात्री गाड़ियों की दैनिक औसत संख्या इस प्रकार रही:—

वर्ष	पिछले वर्ष की तुलना में यात्रियों की संख्या में वृद्धि (+)/कमी (−) (मिलियन में)	पिछले वर्ष की तुलना में चलाई गई गाड़ियों की दैनिक औसत संख्या में वृद्धि
1988–89	−292	126
1989–90	+153	178
1990–91	+189	10

1989-90 की तुलना में 1990-91 में गाड़ियों की संख्या में कम वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि खाड़ी संकट तथा देश में कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति के कारण बहुत सी यात्री गाड़ियों को रद्द करना पड़ा ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा सरकारी आवास का आवंटन

1837. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन, मकानों के पात्र व्यक्तियों को मकानों का आवंटन करता है;